



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन 1940 (श10)
(सं0 पटना 325) पटना, मंगलवार, 5 मार्च 2019

सं०-को०प्र०/कम्प्यूटर-02/2017-2225
वित्त विभाग

संकल्प
5 मार्च 2019

विषय :- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नगद प्रबंधन उत्पाद सेवा (Cash Management Product Services) के माध्यम से लाभूकों/प्राप्तकर्ताओं के बैंक खाते में सीधे भुगतान करने की व्यवस्था को अपनाने तथा सरकारी कोष से लाभ प्राप्त करने वाले लाभूकों के खाते में DBT करने हेतु आधार नंबर अनिवार्य करने के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की व्यवस्था की गयी है । सरकार की अपेक्षा रही है कि राज्य के कोषागारों से राशि की निकासी कर बैंक खातों में संचित नहीं रखा जाय अपितु कोषागारों से सरकारी राशि सीधे प्राप्तकर्ताओं के बैंक खाते में अंतरित किया जाय । इससे लाभूकों को पारदर्शिता के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र प्राप्त होता है ।

2. इस हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित ई-कुवेर पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभूकों के बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था की गयी है । प्रयोग के तौर पर सिंचाई भवन कोषागार में संबंधित राज्यकर्मियों के वेतन भुगतान हेतु क्रियान्वित किया गया है ।

3. राज्य के करीब 72 कोषागारों का संव्यवहार पूर्व से उससे संबंधित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किया जाता है । भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऑनलाइन भुगतान हेतु “Cash Management Product Services (CMPS)” नामक एक पोर्टल बनाया गया है । इसके माध्यम से भी कोषागारों से विपत्र पारित होने के साथ ई-पेमेन्ट का फाइल तैयार किया जायेगा तथा SBI के CMPS पर अपलोड कर दिया जायेगा। विपत्र से संबंधित सभी लाभूकों/प्राप्तकर्ताओं के बैंक खाते में राशि क्रेडिट हो जायेगी । अतः कोषागार से सीधे लाभूकों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) करने हेतु RBI के e-Kuber के अलावे SBI के CMPS का उपयोग करने से शत-प्रतिशत DBT के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है ।

4. राज्य में ऑनलाइन DBT लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लाभूकों का विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। भुगतान के पूर्व लाभूकों के बैंक खाता का सत्यापन विभिन्न बैंकों से ऑनलाइन करने से DBT के माध्यम से भुगतान असफल नहीं होंगे। PFMS के द्वारा लाभूकों के बैंक खाता का सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन राज्य पोर्टल CFMS के माध्यम से भुगतान करने पर उनके द्वारा यह सुविधा नहीं दी जाती है। भारतीय स्टेट बैंक राज्य के लिए लाभूकों के खाता सत्यापन की सुविधा देने को तैयार है।

5. अतः निर्णय लिया गया है कि :-

- (i) CFMS के माध्यम से ई-भुगतान के लिए RBI e-Kuber Portal के अतिरिक्त SBI के CPMS Portal के माध्यम से सीधे लाभूकों के बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू की जाय। परंतु किसी एक कोषागार में एक ही व्यवस्था लागू रहेगी।
- (ii) एक कोषागार में ई-भुगतान हेतु या तो e-Kuber RBI या CMPS पोर्टल का उपयोग किया जायेगा।
- (iii) CMPS का CFMS से Integration हेतु व्यवस्था करने तथा ई-भुगतान के क्रियान्वयन, लेखांकन की प्रक्रिया विहित करने एवं कोषागारों का भुगतान व्यवस्था निर्धारण हेतु वित्त विभाग को प्राधिकृत किया जाय।
- (iv) CFMS के अंतर्गत सरकारी खजाने से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नगद या वस्तु के रूप में लाभ प्राप्त करने हेतु लाभूकों एवं प्राप्तकर्ताओं के लिए आधार नंबर को अनिवार्य किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 325-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>